RAJYA SABHA

Thursday, The 3rd May, 1979/The 13th. Vaisakha, 1901 (Saka)

The House met at eleven of the clock. Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Indents of coal by the Cement industry

*121. SHRI PRAKASH MEHROTRA: f

SHRI T. ANJIAH:

SHRI JAGJIT SINGH ANAND;

Will the Minister of INDUSTRY be pleaded to state:

Ca) what is the total number of indents of coal by the cement industry and how much of it is being supplied to the industry; and

(b) what is the loss of production in the cement industry due to short supply of coal during the current year?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) A statement i3 laid on the Table of the House.

(b) It is not possible to estimate precisely the loss of production in the cement industry due to short-supply of coal alone, as there are several other factors like shortage of power and railway wagons, mechnical breakdown and labour unrest which also eause loss of production.

Statement

The coal linkage of Cement Industry for the period January-March, 1979 was 5.38 lakh tonnes per month. The actual receipts of coal by the Cement Production Units month wise during January-March, 1979 are as under: —

Month	Monthly coal linkage (Tonnes)	Quantity received (tonnes)	% of coal receipts to linkage
January, 1979	537700	408293	76
February, 1979	537700	419800	78
March, 1979	537700	409969	76

श्री प्रकाश महरोत्रा : मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी स्वयं जानते हैं कि सीमेंट की सप्लाई और डिमांड में एक बहुत बड़ा गैप है और स्वयं वहां दो वर्ष से सतत प्रयास कर रहे हैं कि इस गैप को किसी प्रकार से कम किया जाय। उन्होंने अपनी कंसल्टेटिव कमेटीज की मीटिंग्स में भी कहा कि वह एडीशनल कैपेसिटी दे रहे हैं। अभी एनाउन्समेंट आया है कि 9 लाख टन की एडीशनल कैपेसिटी की फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में लग रही है। जो प्रोजेंट कैपेसिटी है उस का मैक्सिमम और आप्टिमम यूटिलाइजेशन हो इस का प्रयास हो रहा है। मिनी सीमेंट प्लान्ट लगाने की बात भी चल रही है, यद्यपि एक भी प्लान्ट अभी तक नहीं लग पाया है। एक तस्वीर तो यह है और दूसरी तस्वीर यह है कि पिटहेड पर कोल के माउन्टेन्स बन गये हैं। उसको

The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Prakash Mehrotra.

मूब करने के लिये वैगन्स नहीं हैं। वैगन इंडस्ट्री का यह हाल है कि वैगन बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रासली ग्रंडरयूटिलाइज्ड है। उसकी कपेसिटी के अनुसार उनके पास आर्डर्स नहीं हैं। एक ग्रोवरग्राल तस्वीर यह है। आज कोल की शार्टेज की वजह से 19 फैक्टरियां बंद हैं और माननीय मंत्री जी ने खुद अपने उत्तर में यह कहा है कि 77 परसेंट उनका जो इंडेंट है कोल का केवल उस को वह मीट कर पा रहे हैं और उसके फलस्वरूप जनवरी और मार्च के महीने में करीब करीब एक लाख टन सीमेंट का प्रोडक्शन कम हुआ है। तो मैं माननीय मंत्री जी से कटेगोरिकली यह जानना चाहूंगा कि क्या वह टाइम बाउन्ड प्रोग्राम बना रहे हैं इन डिफिकल्टीज को मीट करने के लिये या कोई योजना उनके हाथ में है कि जो उन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री और इनर्जी मिनिस्ट्री से मिल कर बनायी हो? और क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि अगले 6 महीनों में उनके प्रयत्नों का क्या असर होगा?

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : सभापति जी, इस मसले पर कोई टाइम बाउन्ड प्रोग्राम की बात नहीं हो सकती, लेकिन इस समस्या को हल करने की दृष्टि से हम इस काम में लगे हुए हैं। कैबिनेट की एक सब-कमेटी है और उस कमेटी के माध्यम से विशेष कर रेल और कोयला इन दोनों की जो समस्या है उस को दूर करने के काम में हम लग हुए हैं। यह सही है कि आंध्र प्रदेश में 9 लाख टन का एक नया कारखाना हम लगाने जा रहे हैं और कुल मिला कर आज जो स्थिति है उसमें अगले 5 वर्षों के भीतर देश में सीमेंट के उत्पादन की क्षमता कम से कम दुगनी करने का काम जारी है और उसको हम पूरा कर पायेंगे।

श्री प्रकाश महरोत्रा : मान्यवर, जितनी जटिल समस्या प्रोडक्शन की है उतनी ही जटिल समस्या डिस्ट्रिब्यूशन की भी है। आज स्थिति यह है कि मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता सदन का लेकिन अपने व्यक्तिगत अनुभव की बात बताना चाहता हूं कि, एक एक, दो दो बोरी सीमेंट के लिये चार चार और छः छः महीने तक भागना पड़ता है। मुझे खुद अक्तूबर में दो बोरी सीमेंट चाहिए थी। वह मुझे जाकर फरवरी के अंत में मिली। तो डिस्ट्रिब्यूशन एक दूसरी अहम चीज है और उसमें सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट से बात कर के क्या आप कोई ऐसी योजना बना रहे हैं कि कम से कम जो प्रोडक्शन है उस का प्रापर डिस्ट्रिब्यूशन हो जाय। सही प्राइस पर तो सीमेंट मिलती नहीं है, ब्लेक मार्केट में 40 रुपये बोरी में लखनऊ में सीमेंट मिलती है आज दिल्ली में स्थिति यह है कि दिल्ली से 25 मील दूर एक स्पूरियस सीमेंट बनाने का कारखाना है जिसमे कोयला पीस कर सीमेंट के साथ मिला कर बेचा जा रहा है। तो इसकी तरफ क्या आप का ध्यान है और इस बारे में आप क्या करने जा रहे हैं?

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : एक तो सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि करने की बात है जिस पर हम लगे हुए हैं। जहां तक वितरण का सवाल है, चूंकि यह शिकायतें काफी हैं इस लिए हम ने राज्य सरकारों से कहा। मौजूदा स्थिति का व्यापारियों की ओर से लाभ उठाने का प्रयास चल रहा है। तो हम ने राज्य सरकारों से कहा कि वह वितरण की जिम्मेदारी वे अपने हाथ में लें। अभी तक 14 राज्य सरकारों ने यह जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है और जहां वे इस काम में लगी हैं वहां ये यह शिकायतें कुछ कम हो गयी हैं। इस मामले में अभी दो चार राज के लिये पहले हम लोगों ने चर्चा की थी और प्रधान मंत्री जी खुद राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखने का जा रहे हैं जिसमें वितरण में ये जो झंझट दिखाई दे रही है इनको दूर करने में राज्य सरकारों को भी विशेष रूप से सहयोग करने को कहा जाएगा।

श्री टी० अंजैया : सभापति जी, मंत्री महोदय, ने बताया कि सीमेंट इंडस्ट्री की इंडस्ट्री है और हमेशा हम लोग शुगर इंडस्ट्री को टेक ओवर करने या टक्सटाइल इंडस्ट्री की टेक ओवर करने के बारे में सोचते हैं तो क्यों नहीं सीमेंट इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया जाए क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री डवलपमेंट में, प्रोजेक्ट्स में, सड़कें बनाने में सब जगह आवश्यक है और आप जानते हैं कि सीमेंट आज ब्लैक मार्केट में बिकता है। इसलिए एक तरफ से सीमेंट की प्राइस बढ़ती जा बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ वर्कर्स की वेजेज बढ़ी नहीं है। तो क्या मंत्री महोदय इस बारे में सोचेंगे और तमाम जो सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं उनको नेशनलाइज करने के बारे में विचार करेंगे?

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : सभापति महोदय, सीमेंट के कर्मचारियों के वेतन के बारे में कोई शिकायत नहीं है। अभी एक बोर्ड आफ आर्बिट्रेशन उन लोगों की ओर से बनाने में आया था जिसमें इंडस्ट्री और लेबर दोनों हैं। उनका जो निर्णय आया है वह तीनों बार्ड के सदस्यों की राय से निर्णय हुआ है जिसको सीमेंट उद्योग ने पूरी तरह से माना है। इस पर अमल करने का काम जारी है।

सीमेंट कारपोरेशन ग्राफ इंडिया जो सरकारी क्षेत्र में कंपनी है उसके कुल काम को बढ़ाने की दिशा में कदम उठा चुके हैं और अगले 10 वर्षों में हम यह अन्दाज लगाते हैं कि 1 करोड़ 17 लाख टन सीमेंट उत्पादन की क्षमता सीमेंट कार-पोरेशन के हाथ में रहेगी । इसके अलावा, कुछ राज्यों में भी उद्योग हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के हाथ चुरक और डाला में दो बड़े कारखाने हैं जिनको उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है। दूसरे क्षेत्रों में भी ग्राइंडिंग यूनिट्स और कंपोजिट सीमेंट यूनिट्स लगाने की दिशा में हम लोग लगे हुए हैं। इसलिए वर्तमान व्यवस्था में इस समय फर्क करने की आवश्यकता हम नहीं समझते।

SHRI JAGJIT SINGH ANAND: Sir, the hon. Minister has supplied information regarding (a) which shows that 25 per cent less coal is coming to cement factories during the last three months than ordered. But the reply to part (b) is very vague. Instead of concretely telling us what the contribution of the short-supply of coal in the under-production of cement is, he has tried to bring in other factors like railway w'agons and all that. Now, we very well know that in the Parliamentary Party of the ruling party there was a quarrel among the Energy Ministers, the Railway Minister and the Industry Minister about the production of steel and cement and whether the shortage of coal or cement or non-availability of wagons was to be Warned. The Energy Minister was saying that '20 million tonnes of coal is available and that the Railway Minister was not taking it fact and that this coal might burn up the country. Now he has again referred to railway wagons. He should specifically tell us how much more production would have been possible if coal was supplied in sufficient quantities to cement factories, and what amount of cement is being imported these days, and to what extent the import of cement would have been cut down and the amount of foreign exchange that would have been saved thus. Secondly, Sir, he has told us what he will do after ten years and that after ten years the State units under the Government would be producing so much. But, will the common people, who are suffering on account of the acute shortage of cement, whose price is three times more than its declared price, have to wait for the moon and wait for these ten years, which this Government is not going to last? Will he, at least; take immediate measures to seize all the production at the factory-gates and get it disributed as part of the essential I supplies scheme which is being introduced from 1st July 1979? Is he aware that cement produced in Suraj-pur in Punjab is exported to Madhya Pradesh and cement produced in Rajasthan is brought to Punjab and I see that all that duplication and pressure on railways is reduced? Will he assure that in order to bring down the price of cement close to the price announced by the Government, he will take steps to seize production at the factory gates and get it distributed as an essential supply through a machinery, with the help of the State Governments of course.

SHRI GEORGE FERNANDES; I have already pointed out that cement distribution has been taken over by a large number of State Governments, by U.P., Punjab, Haryana, Madhya Pradesh, Maharashtrt, Karnataka, West Bengal etc. They have taken over distribution of cement.

SHRI SURENDRA MOHANTY: Is the allocation made by you?

SHRI GEORGE FERNANDES: Allocation is made on the total quantity that is produced. You cannot allocate something that is not produced. When you have certain quantity of cement produced, you allocate by a certain formula that has been evolved. As far as the problem

of overcharging by the trader is concerned, this is a matter where we are constantly persuading the State Governments requesting them to see that they take effective measures to prevent it. It is for them to do it and I am sure efforts on the part of the State Governments, it should not be a difficult problem to prevent blackmarketing in cement. There is shortage of cement; nobody says that theTe is no shortage. When I referred to a 10-year plan, I was talking in terms of take-over of cement industry. The Cement Corporation of India has a 10-year perspective plan in which it is going to increase its own capacity from the existing million plus tonnes to 17 million tonnes. That was the' point that I was making. I was not trying t0 suggest that I should plan only for the duration of my Government. Because the previous Government planned only for their duration, today the country is experiencing black-market and shortage of cement. I am sure the hon. Member is capable of understanding this price is three of understanding this simple thing. I would like to plan for not 10 years, but for 20 years, 30 years and 40 years. That is how I would like to look at this problem. The hon. Member referred to some quarrel between the various Ministers. There is no quarrel. What We are trying to do is to identify the problem and find out a solution. We are importing cement. Last year we imported 1.5 million tonnes; during the current year, we are importing 2 million tonnes. We are importing it in the context of the shortage that we are having. Because of coal shortage, there has been a shortfall in cement production. That is a short-term problem which we are trying to sort out. The hon. Member asked a pointed question about actual loss in cement production because of shortage of coal. In January, 1979, it was 76,000 tonnes; in February 1979, it was 42,000 tonnes; in March 1979, the provisional figure is 56,000 tonnes. Figures for April are not available. This is about, the loss that we are sustaining. But I can assure the hon. Member that we are doing everything that is possible to see that coal supply to the cement plants is maintained.

श्री प्रेम मनोहर : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि मिनी सीमेंट प्लांट्स अपने देश में दो या तीन लगे हुए है, वे ठीक से काम नहीं कर रहे है उनके वर्टीकल फरनेशिस ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो मंत्री महोदय इसके लिए क्या कर रहे हैं ? आदर्श रूप में गवर्नमेंट मिनी सीमेंट प्लांट लगायें किसकी टेकनोलोजी वगैरह सब ठीक रहे इसके लिए आप क्या कर रहे है ? इसके साथ-साथ मैं यह जानना चाहता हूं कि जो अभी हाल में जो आपने हाई लेवल कमेटी सीमेंट पर बनाई थी उसने 35 लाकेशंस छांटकर दिये थे उन लोकेशनों को छांटने में आपने क्या इस बात पर विचार किया है कि जो कोयले की कमी इस समय महसूस हो रही है हर दो साल, तीन साल में जो सीमेंट की शार्टेज हमारे सामने आती है, कभी कोयला नहीं होता तो कभी पावर नहीं होती, तो जो लोकेशन के लिए लेटर आफ इंटेंट देंगे उन लोकेशनों पर ये कठिनाईयां आने वाले समय में नहीं आएंगी ?

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : सभापति महोदय, यह सही है कि आज देश में दो या तीन वर्टीकल शैफ्ट वाले मिनी सीमेंट प्लांट चल रहे है । इनमें से सीमेंट रीसर्च इंस्टीट्यूट जो प्लांट चला रहा है त्रिचरापल्ली के पास तमिलनाडू मे वह ठीक ढंग से काम कर रहा है । वहां सीमेंट जो बन रही है उसका एक तो हम लोग इस टेक्नोलोजी को बताने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे प्रतिदिन 20 टन सीमेंट वहां से मार्किट में बेचने के लिए काम में आ रहा है । इनमें एक तो लखनऊ के पास है वह कोई काम नहीं कर रहा है । उसमें एक जमाने की दिक्कत है । दस वर्षो से वह बंद पड़ा हुआ है । राज्य सरकार, सीमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट और अन्य लोग जो उसको चलाते है उनकी आपस में बातचीत चल रही है । हम कई दिनों से प्रयास में लगे हुए हैं उनकी आपस की समस्या को हल कराने के लिए । उन कारखानों का इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिये, टैक्नोलोजी को बताने के लिये कर रहे हैं । वर्टीकल शैफ्टकिल के बारे में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है । आज तक मिनी सीमेंट प्लांट

लगाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा था। हम पछले एक ग्रसें से इस बारे में बोलते रहे हैं और बहुत से कदम भी उठाये हैं। सीमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने देश भर में कई जगहों को आइडेंटीफाई किया है। अन्य लोगों ने भी और राज्य सरकारों ने भी कई जगहों को आइडेंटीफाई किया है। आज लगभग 50 जगहों पर काम शुरू हो चुका है। इस संबंध में कुछ शुरूआत हो चुकी है और कई जगहों पर कार्य चल भी रहा है। कई जगहों पर पूर्व तैयारी क काम हो रह है। इस समय हमारा अन्दाजा यह है कि हमारे पास करीब दो हजार अर्जियां आ चुकी हैं। वे लोग सीमेंट के छोटे - छोटे कारखाने लगाना चाहते हैं। इतने कारखाने हम लगा भी पाएंगे या नहीं, इस पर हमें विचार करना है और मैं इतने कारखानों की जरूरत भी महसूस नहीं कर रहा हूं। मगर जिन-जिन स्थानों पर लगाना संभव होगा वहां पर हम वर्टीकल शेफ्ट किल टैक्नोलोजी के आधार पर या रोटरी शेफ्ट किल टैक्नोलोजी के आधार पर कारखाने लगाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा एक टैक्नोलोजी रैबा प्रौसेस भी सामने आई है। उसके लिए भी हम प्रयत्नशील हैं और इसको हम अपने देश में लगाना चाहते हैं। इस प्रकार से इन तीनों टैक्नोलोजीज के आधार पर जहां भी सीमेंट के कारखाने लगाए जा सकते हैं उनको हम लगाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : मान्यवर, जनता पार्टी के विभिन्न घटकों में जिस प्रकार का मतभेद और असामंजस्य है उसकी चर्चा में यहां पर नहीं करना चाहता। लेकिन उसके परिणामस्वरूप विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में जो असामंजस्य और मतभेद दिखाई दे रहे हैं उसके कारण आम लोगों को बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। आज के ही समाचार पत्रों में यह छपा है कि वैगनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि कोयले की सप्लाई में वैगनों की कमी नहीं हो पा रही है। रेलवे मिनिस्टर एक बात कहते हैं तो दूसरे मिनिस्टर दूसरी बात कहते हैं। इंडस्ट्री मिनिस्टर तो बहुत जोरों से बोलते रहते हैं। एक मिनिस्टर कहते हैं कि वैगनों की कमी नहीं है और दूसरे मिनिस्टर कहते हैं कि कोयले की कमी नहीं है। इस प्रकार से हमारे देश की गरीब जनता महंगाई और अभाव के चक्कर में पिसती जा रही है। ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री जी से तीन बातें जानना चाहता हूं। पहली बात तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अलग-अलग मंत्रालय और विभागों में सामंजस्य और समन्वय स्थापित करने के लिए कोई प्रयत्न किया है जिससे हमारे देश में जो सीमेंट की कमी हो रही है और उसके उत्पादन में भी जो कमी हो रही है उसको दूर किया जा सके? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले दो सालों में सीमेंट के उत्पादन में कितनी कमी हुई है और तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि सीमेंट के बजाय, क्या आपने कोई वैकल्पिक वस्तु भी तैयार करने का प्रयत्न किया है जिससे कि उसका उपयोग सीमेंट के स्थान पर हो सके और सीमेंट का अभाव दूर किया जा सके?

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : सभापति जी, मैं पहले ही प्रश्न के जवाब में यह बता चुका हूं कि विभिन्न मंत्रालयों में कोआर्डिनेशन का काम कैबिनेट की एक सब-कमेटी कर रही है। इस मामले में किसी प्रकार के असामंजस्य या आपस में मतभेद की कोई बात नहीं है। मैं माननीय सदस्य को यह भी बता दूं कि पिछले साल इस देश में सीमेंट का उत्पादन हुआ वह 96 लाख टन के लगभग हुआ। इस देश में इससे पहले इतना उत्पादन कभी नहीं हुआ। जहां तक कैपेसिटी युटिलाइजेशन का सवाल है, पिछले साल लगभग 90 प्रतिशत कैपेसिटी युटिलाइजेशन हुआ जबकि सीमेंट उद्योग में 85 प्रतिशत युटिलाइजेशन एक अच्छी बात समझी जाती है। ऐसी हालत में यह कहना कि अखबारों में इस प्रकार की बातें छप रहीं हैं, यह उचित नहीं है। अखबार वाले अपनी दृष्टि से कोई बात छापते होंगे। लेकिन जहां तक सीमेंट के उत्पादन का सवाल है, 90 प्रतिशत रिकार्ड कैपेसिटी युटिलाइजेशन पिछले साल किया गया है। इसको मैनटेन करना और उसमें सुधार लाना हमारा फर्ज है और उसको हम करते रहेंगे।

श्री जगदीश जोशी : श्रीमन्, जैसा कि श्री जगजीत सिंह आनन्द ने कहा है कि सूरजपुर का सिमेंट दूसरे राज्यों में भेजा जाता है और दूसरे राज्यों का सीमेंट पंजाब और हरियाणा में भेजा जाता है। इससे न केवल सप्लाई में वैगनों की आवश्यकता होती है बल्कि अन्य भी कई प्रकार की कठिनाईयां पैदा हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस नीति में कोई परिवर्तन करने जा रहे हैं जिससे सीमेंट जिस क्षेत्र में पैदा होता है वहीं पर उसका उपयोग किया जाय अर्थात् जहां पर सीमेंट का उत्पादन होता है उसके आसपास के इलाकों को सीमेंट के वितरण में प्राथमिकता दी जाय? दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्या सरकार ने इस प्रकार की कोई जांच की है कि सतना में जो सीमेंट फैक्ट्री है उसमें इतना इन्फीरियर किस्म-का सीमेंट बनता है कि कोई भी सरकारी इंजीनियर उस सीमेंट को अपने काम में लाने में डरता है? ऐसी हालत में मैं जानना चाहता हूं कि इस सीमेंट कारखाने में जो कि निजि क्षेत्र में है, सुधार लाने के लिए और उसको ठीक करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : सभापति महोदय, सतना में सीमेंट कारखाने के बारे में जोशी जी ने जांच करने की जो आवश्यकता बताई है उसको तत्काल हम करेंगे। जहां तक वितरण का सवाल है, यह सवाल श्री आनन्द जी ने भी पूछा था, यह बात सही है कि पहले इस प्रकार की कुछ कठिनाईयां थीं। पिछले कई महीनों से इस तरफ ध्यान दिया गया है और इस शिकायत को दूर करने की कोशिश की गई है। अब हमारी यह नीति है कि सीमेंट का कारखाना जिस क्षेत्र में है उसके आस-पास सीमेंट का वितरण किया जाय। यही सिलसिला हमारा चल रहा है।

श्री सीताराम केसरी : सभापति जी, मंत्री जी राष्ट्रीयकरण के बहुत बड़े समर्थक भी हैं। मगर

मुझे उनसे यह पूछना है कि आज उत्पादन में मांग के आधार पर जो कमी होती है उसकी पूर्ति के लिए आप आयात करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। इस प्रकार जो अभाव है, जो कमी है, देश वासियों की जो जरूरते हैं उनको आयात करके पूरी करते हैं। परन्तु इसके बावजूद भी आज सीमेंट की कमी है और सीमेंट 50-50 और 60-60 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से ब्लैक में बाजार में बिक रहा है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि उनके पास जो यह खबर आ रही है कि विभिन्न प्रदेशों की सरकारो ने इसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है इसकी वजह से कीमत नियंत्रित है, यह बात गलत है। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि आपके पास दो हजार आवेदन छोटे सीमेंट के उद्योग-धंधों के लिये हैं उनके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि उनमें से कम से कम डेढ़ हजार फोर्ज होंगे जो कि इसका लाइसेंस लेकर खोलेंगे नहीं, इसलिये कि यदि सीमेन्ट का ज्यादा उत्पादन होगा तो बाजार में सीमेन्ट की कीमत घटेगी। इसलिये मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रुप से जानना चाहता हूं कि जनता की डिमान्ड की उत्पादन द्वारा पूर्ति न होने के कारण आप इसका आयात करतें हैं परन्तु इसके बावजूद भी देश में सीमेन्ट का अभाव है और उसकी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, तो इस ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिये आप स्पष्ट रुप से क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : सभापति जी, उत्पादन में वृद्धि करने का मुख्य काम हमारा रहेगा ताकि सीमेंट का अभाव न रहे। उत्पादन में जो कमी महसूस हो रही है उसकी पूर्ति के लिए हम आयात करने का काम कर रहे हैं। हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि जहां सीमेंट की आवश्यकता न हो वहां इसका इस्तेमाल न हो। कुछ और क्षेत्रों में हम प्रयत्न यह कर रहे हैं, जैसे छोटे सीमेंट कारखाने लगाने के मामले में एक और प्रयोग हो रहा है। सभापति महोदय, यह जो चावल का छिलका है, राइस हस्क उसको लेकर 'एस्मो, इस नाम से इस देश में सीमेण्ट बनाने का काम शुरू किया गया है। कर्नाटक में शिमोगा में यह काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के अतारा गांव में यह काम हो रहा है और इस काम को पंजाब और हरियाणा के इलाके में विकसित करने में हम लगे हुएं हैं। जहां जहां चावल की मिलें हैं वहां वहां इस टेक्नालाजी को ले जाने के काम में हम लगे हुए हैं ?

श्री सीताराम केसरी : श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह है कि अभाव की जो आप बात करते हैं उस अभाव की पूर्ति के लिए प्रयास करने के बावजूद आज सीमेण्ट काले बाजार में ऊंचे दामों पर बिक रहा है। इसको रोकने के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं, मेरा यह प्रश्न है।

SHRI SURENDRA MOHANTY: We find from the Statement furnished by the Ministry that the percentage of coal receipts to linkage is of the order of about 76 per cent on an average. In view of that, it cannot be said that lack of coal is a constraint on the production of cement because it is countervailed by the non-utilization of the existing capacity. In view of this and also in view of the import of cement from foreign countries, let the Minister assure the House that he will not encourage an economy of scarcity and shortage, thereby encouraging blackmarketing all through.

Secondly in view of the fact that the Janata Party is ruling right from the Centre down to the States, I would like to know what steps the Government at the Centre from streamlining the State agencies where we find black-marketing being encouraged in the field of cement.

SHRI GEORGE FERNANDES. Sir, the hon. Member is not very accurate when he says that it is not coal that is creating problems. In the month of January 1979 there were 14 cement factories which had to be closed down because there was no coal supply. In the month of February 11 factories had to be closed down and in the month of March there were 10 factories which had to be closed down because there was no coal supply.

SHRI SURENDRA MOHANTY: But your statement does not give those figures.

SHRI GEORGE FERNANDES- The statement relates to a specific question and that question has been answered. In terms of closure of factories this is the problem. And in the month of March there were 36 cement factories where because of inadequate coal supply the situation had become very

critical. Since January the position of about 30 to 38 factories has been varying in term Critically of availability of coal. We have this problem and, as I said earlier, we are trying to xesolve this problem through co-ordination, meetings of Cabinet sub-committees at various levels between the Coal Ministry and the Railway Ministry and the Industry Ministry and other concerned interests.

Sir, in so far as the streamlining of the State agencies is concerned it is true that in some of the State's, the Janata Party has its Government while in other States there are other parties which are having their Governments. The hon. Member is not correct in saying that in all the States the Janata Party has its Government. But the States have their autonomy. I do not believe it is possible for the Government of India to tell the States precisely what to do and what not to do. We have been telling them, where cement distribution is concerned, that it is upto them to see that the kind of black-marketing that is today prevalent in certain parts of the country is stopped and I would once again appeal to the State administrations to take effective steps in this regard.

SHRI SURENDRA MOHANTY: Sir, on a point of order.

MR. CHAIRMAN: No point of order during Question Hour. Mr. Naidu.

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAIDU: According to the hon. Minister's statement several cement factories have been closed down for want of coal. This coal trouble has been going on for the last two or three months and the Cabinet has appointed a Sub-Committee for this. At the pitheads, definitely a lot of coal is available. But the railway wagons are not available to move the coal. Everybody knows this. The Railway Minister is also a labour leader but - he is not able to make the railway people work and move the wagons. Actually I was told that they are going on a 'go slow' policy because the bonus issue has not been settled. That is the main trouble. Now, Sir, the Minister of Industry is also a labour leader.

MR. CHAIRMAN: What is your supplementary?

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAIDU: The railway labourers have also got faith in Mr. Fernandes. Therefore, will he advise them at last to wait till the bonus issue is settled and ask them to move the railway wagons and see that the coal is supplied to the factories.

SHRI GEORGE FERNANDES: I think it will be simplifying the issue to say that it is the railway workers who are not moving the railway wagons. There are a number of problems. The tracks are out-dated. The tracks cannot take additional capacity. There is shortage' of wagons. There are a number of factors which are contributing to the present crisis. Permit me to say, Sir, as I have said earlier, that between the Coal Ministry, the Industry Ministry and the Railway Ministry, these problems are being resolved.

श्री रामेश्वर सिंह : श्रीमान मंत्री जी यह महसूस कर रहे हैं कि सीमेंट की कमी है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हरियाणा में जो डालमिया फेक्टरी है वह बंद होने जा रही है और उसमें दो हजार मजदूर बेकार होने जा रहे हैं, इस पर वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नेन्डीज : इस पर अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस पर कार्यवाही करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा के कारखाने का मामला कुछ अलग ही है। उस कारखाने की ओर से सरकार को सीमेंट अकाउंट में एक्साईज में, श्रमिकों को देने के कई मसले हैं जिनमें करोड़ों रुपया देना है। हम उस पर अभी अलग निर्णय लेने जा रहे हैं।

SHRI VIREN J. SHAH: Will the hon. Minister kindly tell us whether he has received any proposal from any Member of Parliament to transfer power from Kerala to Tamil Nadu so that the Tamil Nadu cement factories can operate and supply cement to

Kerala in exchange for power? Secondly, about the mini-steel plants, is the Minister aware that the applications made to the financial institutions are not yet cleared? I would like to know whether the Government has given any clear directive to the financial institutions to see that the mini-cement plants make progress.

SHRI QEORGE FERNANDES: About the mini-steel plants there have been some problems which have been brought to our notice that gome of the financial institutions have been creating difficulties. We have taken up the matter with the financial institutions and I am sure we will be able to resolve it. It is true that Kerala surplus power has been made available to Tamil Nadu. There were a number of suggestions made. But even before the suggestions came from the Members of Parliament, I had got in touch with the Chief Minister of Tamil Nadu in this connection and also with the Chief Minister of Kerala. The Kerala power has been made available to Tamil Nadu and Tamil Nadu cement is going to Kerala produced with the surplus power which Kerala has made available.

*122. [The questioner (Shri U. R. Krishnan) was absent. For answer vide col. 56 infra.]

Attacks on Christian community in Kashmir

•123. SHRI SHRIKANT VERMA: t

SHRI MAHENDRA MOHAN MISHRA:

SHRI BHAGWAN DIN:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state.-

(a) whether the leaders of the Christian community .in the State of Jammu and Kashmir have sent a communication t0 the Prime Minister, urg_ ing upon him to take immediate steps to protect the members of their Community in view of the continuing attacks on them following the execution of Mr. Z. A. Bhutto; and

(bj whether it is a fact that the All Saints Church in that State was burnt on April 4, 1979 by some rowdies?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI H. M. PATEL): (a) and (b) Yes, Sir.

SHRI SHRIKANT VERMA: I strongly resent the manner in which the question has been transferred to the Home Ministry. Originally it was addressed t0 the Prime Minister who is also here. Why it has happened, I do not know. The letter was written to the Prime Minister.

Of late the Christian community throughout the country is suffering from a sense of insecurity because many atrocities are taking place on them and the Government is giving shelter and patronage to those who commit these atrocities. Not only this, a Bill is being brought jn the name of the Freedom of Religion Bill.

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI: It is an incorrect allegation.

SHRI SHRIKANT VERMA: What are you talking?

MR. CHAIRMAN: You put your supplementary.

SHRI SHRIKANT VERMA. I would like to know from the Home Minister whether the officials present there took any action against the hooligans who were trying to destroy the churches systematically, and if they did not take any action whether any action has been taken against erring officials? Has any of them been suspended because it is reported that the officials were in collusion with the hooligans who in the name

---

The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Shrikant Verma.